

प्रेषक,

आर०के० चौहान,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांक: 10, सितम्बर, 2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु सेंटर आफ एक्सीलेंस के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी जनपद नैनीताल में चल रहे व्यवसाय आटोमोबाइल्स के भवन निर्माण एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण (युवक) देहरादून में चल रहे व्यवसाय इलैक्ट्रिकल्स के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी जनपद नैनीताल में चल रहे व्यवसाय आटोमोबाइल्स के भवन निर्माण एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण (युवक) देहरादून में चल रहे व्यवसाय इलैक्ट्रिकल्स के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार ने अनुमोदित आंगणन रूपये 40-40 लाख के सापेक्ष अपने पत्र संख्या DGET-35(4)(43)/2005/CWUCHE L-PCT/CPIU, Dated : 30 Dec, 2005 द्वारा केन्द्रांश के रूप में प्रथम किस्त रूपये 15 लाख (रूपये 7.5-7.5 लाख प्रत्येक) अवमुक्त किये, उक्त के कम में शासनादेश संख्या 163/VIII/10-प्रशि0/05, दिनांक 13 फरवरी, 2006 के द्वारा रूपये 15 लाख (रूपये 7.5-7.5 लाख) केन्द्रांश एवं रूपये 10 लाख (रूपये 5-5 लाख) राज्यांश इस प्रकार कुल रूपये 25 लाख अवमुक्त किये गये हैं।

2- अतः उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या : CDGET-35(4)(49)/ 2005/CW Utt-PCT/CPIU, Dated : 22 nd May, 2007 के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी जनपद नैनीताल में चल रहे व्यवसाय आटोमोबाइल्स के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रूपये 15 लाख एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून में चल रहे व्यवसाय इलैक्ट्रिकल्स के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रूपये 15 लाख इस प्रकार कुल रूपये 30 लाख अवमुक्त किये हैं। उक्त अवमुक्त केन्द्रांश रूपये 30 लाख के सापेक्ष राज्यांश रूपये 5 लाख (प्रत्येक हेतु रूपये 2.5-2.5 लाख) इस प्रकार कुल रूपये 35 लाख (रूपये पैंतीस लाख मात्र) (प्रत्येक हेतु रूपये 17.50-17.50 लाख = 35 लाख) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आबंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

- 4- भवन निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 5- उक्त धनराशि भारत सरकार के उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जाए।
- 5- उक्त धनराशि को 31/3/2008 तक पूर्ण व्यय करते हुये उपयोगिता तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु अनुदान संख्या-16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार, 03-प्रशिक्षण-आयोजनागत-00, 003-दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें, 0101-योजना आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (75 प्रतिशत के 0 रा0) के अन्तर्गत मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। यह आंबटन निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के लिए किया जा रहा है।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 800/वित्त अनु0-5/2007, दिनांक: 21 अगस्त, 2007 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 625 (1)/VIII/07-10-प्रशि0/2006, तददिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
- 4- अपर सचिव, वित्त-बजट।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- वित्त अनुभाग-5
- 7- नियोजन विभाग।
- 8- अनुसचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 22-5-2007 के क्रम में सूचनार्थ।
- 9- एन0आई0,सी0 सचिवालय परिसर।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।